

उत्तराखंड उच्च न्यायालय,

नैनीताल

9th नवंबर, 2022

समक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी

याचिका (एम/एस) संख्या 2520/2022

मध्य:

चरण सिंह और अन्य

याचिकाकर्ता

(द्वारा श्री टी. ए. खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सदफ, अधिवक्ता की सहायता से, याचिकाकर्ता के वकील श्री विनय भट्ट, अधिवक्ता का संक्षिप्त विवरण रखते हुए)

एवम्

श्रीमती विमला देवी और अन्य

प्रतिवादीगन

(श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3 के अधिवक्ता और श्री योगेश सी तिवारी, उत्तराखंड राज्य/प्रतिवादी संख्या 7 के स्थायी अधिवक्ता)

निर्णय

संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर, उधम सिंह नगर द्वारा पारित 30.11.2021 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा दायर संशोधन को भी खारिज कर दिया गया, जिसे इस रिट याचिका में भी चुनौती दी गई है।

२- याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में प्रतिवादी संख्या १ से ३ द्वारा दायर राजस्व वाद संख्या 22/15 वर्ष 2015-16 में प्रतिवादी हैं। वादपत्र प्रकथन के अनुसार, अभियोक्ता नं. १ के ससुर और अभियोक्ता नं. २ और ३ के पिता स्वर्गीय परमदेव सिंह, कृषि भूमि के संबंध में हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ भूमिधर थे, जिनकी माप खसरा नं. २९-ख और ३० च, गांव झागरपुरी, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है, परमदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात वादियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित किए गए थे।

३- वादपत्र में अग्रेतर यह अभिवचन किया गया कि स्वर्गीय परमदेव सिंह का भतीजा बेचन सिंह, स्वर्गीय परमदेव सिंह के अभिकर्ता के रूप में प्रश्नगत भूमि की देख-रेख कर रहा था, क्योंकि परंदेव सिंह जिला मऊ (उत्तर प्रदेश) में रहते थे, परमदेव सिंह, बेचन सिंह की मृत्यु के पश्चात जब फरवरी, २००८, में उधम सिंह नगर जिले के नंदपुर गांव में आए, तब उन्हें यह पता चला कि

स्वर्गीय बेचन सिंह ने समझौता कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत भूमि के संबंध में उनका नाम धोखाधड़ी से दर्ज कराया था, और उसके बाद उसने प्रतिवादी नं. १, २ और ३ (यहां याचिकाकर्ता) के पक्ष में अवैध रूप से उसी भूमि को बेच दिया था। वादियों ने आदेश दिनांकित १०-१२-१९९६ को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा बेचन सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था, और वादियों द्वारा दाखिल आवेदन को सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित ७-११-२००८ द्वारा स्वीकार किया गया था, और वादियों का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिधर के रूप में फिर से दर्ज किया गया था। अग्रेतर यह अभिवचन किया गया कि स्वर्गीय बेचन सिंह ने अभियोक्ता संख्या -१ के पति स्वर्गीय रामजनम सिंह के जाली हस्ताक्षर के साथ एक पारिवारिक समझौते का निर्माण किया था, हालांकि वह पिछले ३१ वर्षों से लापता था और उसकी सिविल मृत्यु को २००३ के सिविल मुकदमा संख्या १४८३ में जिला मऊ में सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था। मुकदमा में, याचिकाकर्ताओं ने एक घोषणा की मांग की कि स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा २६-०४-१९९९ और ०४-०१-२००० को प्रतिवादी संख्या १, २ और ३ के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख अमान्य हैं। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि मुकदमा सम्पत्ति का कब्जा उन्हें सौंप दिया जाए।

4- याचिकाकर्ता, जो वाद में प्रतिवादी संख्या १, २ और ३ हैं, ने पहले सी. पी. सी. के आदेश ७ नियम ११ के अंतर्गत इस वाद हेतुक एक आवेदन दाखिल किया था कि राहत 'ए' और 'बी' के लिए भुगतान की गई न्यायालय फीस अपर्याप्त है और राहत 'सी' के लिए कोई न्यायालय फीस का भुगतान नहीं किया गया है और अग्रेतर यह कि मुकदमा, वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है।

याचियों द्वारा दायर आवेदन का निपटान विद्वान विचारण अदालत द्वारा दिनांक 06.08.2019 के आदेश के माध्यम से किया गया, जिसमें वादियों को राहत 'ए' और 'सी' के लिए अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

5- इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 से इस तर्क के साथ एक और आवेदन दायर किया कि विक्रेता (बेचन सिंह) 14 जनवरी, 1996 को एक पारिवारिक समझौते के माध्यम द्वारा प्रश्नगत भूमि का मालिक बन गया था, और जब याचियों ने भूमि खरीदी थी, तब स्वर्गीय बेचन सिंह कथित भूमि का पूर्ण स्वामी बन गया था। यह अग्रेतर प्रतिवाद किया कि वादियों के बहाली आवेदन पर सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने एक संशोधन दायर किया और विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊं ने दिनांक 10.03.2011 के आदेश द्वारा मामले को सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया, और रिमांड आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 10.03.2011 को पारित निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी गई, इसलिए, जब तक वादियों द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष दायर बहाली आवेदन में योग्यता पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वादियों द्वारा दायर घोषणा के लिए मुकदमा चलाने योग्य नहीं है, नतीजतन, याचिकाकर्ताओं के वाद हेतुक उपलब्ध नहीं है। यह अग्रेतर तर्क दिया गया कि मुकदमा काल बाधित है।

६- उक्त आवेदन को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर द्वारा दिनांक 30.11.2021 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के दिनांक 30.11.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए संशोधन दायर किया, जिसे विद्वान आयुक्त, कुमाऊं डिवीजन द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश और आयुक्त द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

८- विद्वान सहायक कलेक्टर ने मामले पर गहनता से विचार किया, और आदेश ७ नियम ११ cpc के तहत दायर याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करने का वैध कारण दिया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू-राजस्व अधिनियम की खंड 54 से संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश की बहाली के लिए वादी द्वारा फाइल किया आवेदन यह घोषणा करने के लिए कि विक्रय विलेख अकृत और शून्य हैं, नियमित मुकदमा को वर्जित नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की खंड 40-ए को भी संदर्भित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश के स्वामित्व की घोषणा के लिए नियमित मुकदमा में कोई प्रभाव नहीं होगा। विद्वान विचारण अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 से याचियों के आवेदन पर दिनांक 06.08.2019 को पारित पहले के आदेश का भी उल्लेख किया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की आपत्ति है कि वादपत्र में कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया है, को खारिज कर दिया गया था।

९- विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने भी इस मामले पर विस्तार से विचार किया है और रिट याचिका में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा (एम/एस) संख्या 668/2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 28.10.2021, को पुनः प्रस्तुत किया है। सह-समन्वय पीठ के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित रिमांड आदेश को दी गई चुनौती असफल थी।

10- यह न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत है।

11- याचियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि नीचे के विद्वान न्यायालयों ने यह विचार नहीं करने में गलती की कि मुकदमा कानून द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात दायर किया गया था, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेश को खारिज किए जाने योग्य है।

12- प्रतिवादी नं. १, २ और ३ के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि उनके मुवक्किलों ने पहले एक सिविल न्यायालय के समक्ष एक घोषणात्मक वाद दाखिल किया था, यद्यपि याचियों ने एक रिट याचिका दाखिल करके सिविल न्यायालय के समक्ष वाद की संधारणीयता पर सवाल उठाया, और इस न्यायालय की एक पीठ ने दिनांक ०२-०९-२०१५ को निर्णय दिया कि कृषि भूमि के संबंध में सिविल वाद अनुरक्षणीय नहीं है और उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप, याचियों को राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल करना था। वह अग्रेतर प्रस्तुत करता है कि उसके मुवक्किल उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले के निवासी हैं और उन्हें पता नहीं था कि उनकी भूमि स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा चुपके से बेच दी गई थी, और जब उन्होंने विक्रय विलेखों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने तुरंत मुकदमा दायर कर दिया, इस प्रकार मुकदमा दायर करने में उनकी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ और बिक्री विलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की तिथि से सीमा की अवधि का हिसाब लगाया जाना है।

13- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 द्वारा वादपत्र को नामंजूर किये जाने से न्यायालय को किसी सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए एक कठोर शक्ति प्रदान की गई है। आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है।

पोपट एंड कोटेचा सम्पति बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि, जो (2005) 7 एस. सी. सी. 510 में रिपोर्ट की गई है, को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“आदेश 7 के नियम 7 का खंड (डी) वाद की बात करता है, जैसा कि मुकदमा के कथन से प्रतीत होता है कि उसे किसी कानून द्वारा वर्जित किया गया है। विवादित प्रश्नों का निर्णय, आदेश 7 के नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन पर विचार के समय नहीं किया जा सकता है, केवल उन मामलों में लागू होता है जहां वादी द्वारा वाद में दिया गया बयान, बिना किसी संदेह या विवाद के यह दर्शाता है की मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है।”

14- यहाँ इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी वाद के मुकदमा को खारिज किया जा सकता है, यदि मुकदमा को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह पाया जाता है कि वाद परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। यद्यपि, कभी कभी, परिसीमा का तर्क विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिस पर फैसला मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य लेने के पश्चात् ही किया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालासरिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम हनुमान सेवा ट्रस्ट, (2006) 5 एससीसी658 में रिपोर्ट किया गया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“पार्टियों के वकीलों को सुनने के पश्चात, वादपत्र, आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत आवेदन और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को पढ़ने के पश्चात हमारा यह मत है कि वर्तमान वाद को उचित अभिवचन, परिसीमा के मुद्दे को तैयार करने और साक्ष्य लेने के बिना परिसीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। परिसीमन का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। मुकदमा के पढ़ने पर वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता है कि वाद समय से वर्जित है।”

15- आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. से न्यायालय को उपलब्ध शक्ति की व्याप्ति पर पी. वी. गुरु राज रेड्डी बनाम पी. नीरधा रेड्डी, (2015) 8 एस. सी. सी. 331 में रिपोर्ट किए गए मामले में विचार और चर्चा की गई थी, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय के लार्डशिप्स ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना न्यायालय में दहलीज पर सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए प्रदत्त कठोर शक्ति है। अतः, आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्तें कठोर हैं और न्यायालय द्वारा लगातार ऐसा अभिनिर्धारित किया गया है। मुकदमा के प्रकथनों को यह पता लगाने के लिए कि क्या यह वाद हेतुक को प्रकट करता है या क्या वाद किसी कानून से वर्जित है, समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग के चरण में, लिखित बयान में या वादपत्र के अस्वीकृति के लिए आवेदन में प्रतिवादियों का पक्ष पूरी तरह से महत्वहीन है। यह मात्र तभी है जब मुकदमे में प्रकथन प्रथमदृष्टया वाद हेतुक का खुलासा नहीं करते हैं या उनके पढ़ने पर वाद किसी कानून के अन्तर्गत वर्जित प्रतीत होता है, मुकदमा को अस्वीकार किया जा सकता है। अन्य सभी स्थितियों में, मुकदमे के दौरान दावों का न्यायनिर्णयन करना होगा।”

१६- प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता, (2007) 10 एससीसी 59 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। कथित मामले में, विद्वान विचारण अदालत ने इस आधार पर मुकदमे को अस्वीकार कर दिया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"21. जैसा कि पहले कहा गया है, आदेश 7 नियम 11 (घ) के वादपत्र की अस्वीकृति के लिए दायर आवेदन में एक आदेश पारित करने से पहले, पूरे वादपत्र प्रकथनों को सत्यापित करना उचित है। उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि मुकदमा संख्या 183/1974 में पारित डिक्री वर्ष 1986 में अभियोक्ता के संज्ञान में आई, जब मुकदमा संख्या 424/1989 का शीर्षक एसेमा आर्किटेक्ट बनाम राम प्रकाश मुकदमा किया गया था, जिसमें पहले की डिक्री की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई थी और उसके बाद उसने जल्द से जल्द कदम उठाए और घोषणा के लिए और कब्जे के लिए विकल्प में मुकदमा मुकदमा किया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 के अनुसार, ज्ञान की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था। वादपत्र में उल्लिखित ज्ञान को अपर्याप्त और अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है। आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर निर्णय करते समय, कुछ पंक्तियों या पैरा को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसके वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए पूरे अभिवचनों को पढ़ना होगा। हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों वादपत्र में कथित प्रासंगिक प्रकथनों को लागू करने में विफल रहे।

22. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि लिखित बयान दाखिल करने के पश्चात सीमा, विचारण सहित मुद्दों की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात वादी की प्रतिपरीक्षा की गई थी, उसके बाद विचारण की समाप्ति से पहले, वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अपीलार्थी-वादी को इस आशय का कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था कि उसके द्वारा किया गया मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है।

23. पूरे वादपत्र प्रकथनों पर गौर करने पर, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने वादपत्र में उपलब्ध सभी सामग्रियों पर ध्यान दिए बिना विलंब के आधार पर इसे अस्वीकार करने में त्रुटि की है वह भी वाद में उपलब्ध सभी सामग्रियों पर ध्यान दिए बिना। उच्च न्यायालय ने भी विचारण अदालत के आदेश की पुष्टि करने में यही त्रुटि की है।

२४. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमने मुकदमा संख्या 318/2003 में सिविल न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित 20-2-2006 के विचारण न्यायालय के आदेश और आर. एफ. ए. सं. 188/२००६ में उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 27-4-2006 को पारित निर्णय को अपास्त कर दिया। परिणामस्वरूप, सिविल अपील को अनुज्ञात किया जाता है और सिविल न्यायाधीश को वाद को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने और इस निर्णय के प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः गुणागुण के आधार पर उसका

निपटान करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसीमा के प्रश्न के अलावा, हम दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावे के गुण दोष पर नहीं गए हैं। कोई खर्च नहीं।

१७- श्रीहरि हनुमानदास टोटाला बनाम हेमंत विट्ठल कामत और अन्य (2021) 9 एस. सी. सी. 99 में रिपोर्ट किए गए मामले में हाल ही में दिए गए एक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या रेस जुडीकेटा वाद अस्वीकृति का आधार हो सकता है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के क्षेत्र का विस्तार से विश्लेषण किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 से 22 नीचे दिए गए हैं:-

"18. इस स्तर पर, उन विनिश्चयों के प्रति निर्देश करना आवश्यक होगा जो विशेष रूप से इस प्रश्न से संबंधित हैं कि क्या वादपत्र की अस्वीकृति का आधार या आधार रेस जुडीकेटा हो सकता है। कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा [कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा, (2008) 12 एस. सी. सी. 661] में विचारण न्यायाधीश ने विभाजन के वाद में मुकदमा के नामंजूर किए जाने के लिए एक आवेदन मंजूर किया था और इसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 (घ) की परिधि की जांच की और यह मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. 668-69, पैरा 21-22)।

२१. "संहिता के आदेश 7 के नियम 11 (घ) का प्रयोग सीमित है। यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि मुकदमा किसी भी कानून के अन्तर्गत वर्जित है। ऐसा निष्कर्ष वादपत्र में किए गए प्रकथनों से निकाला जाना चाहिए। हमारे मत में, आदेश 7 के नियम 11 के विभिन्न खंडों को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि इस दिए गए मामले में, वादपत्र के अस्वीकृति के लिए एक आवेदन उसके विभिन्न उपखंडों में निर्दिष्ट एक से अधिक आधार पर दायर किया जा सकता है, उस प्रभाव का एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (डी) को लागू करने के लिए वादपत्र में किए गए कथन प्रासंगिक होंगे। इस उद्देश्य के लिए कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। किसी न्यायालय की ओर से क्षेत्राधिकार की अभाव को संहिता के विभिन्न चरणों और विभिन्न प्रावधानों से लागू किया जा सकता है। संहिता का आदेश 7 नियम 11 एक है, आदेश 14 नियम 2 दूसरा है।

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) को लागू करने के प्रयोजन के लिए, किसी भी मात्रा में साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। मामले की योग्यता पर जो मुद्दे पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं, वे उस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे। उक्त प्रावधान के तहत सभी मुद्दे किसी आदेश की विषय-वस्तु नहीं होंगे।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अग्रतर अभिनिर्धारित किया (कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा, (2008) 12 एस. सी. सी. 661), एस. सी. सी. पी. 669, पैरा 23-25)।

23. " रेस जुडीकेटा के सिद्धांत, जब आकर्षित होंगे, संहिता की खंड 12 को ध्यान में रखते हुए, एक और वाद को वर्जित कर देंगे। कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न से संबंधित प्रश्न जिसके लिए न मात्र मुकदमे की बल्कि अन्य साक्ष्य की भी जांच की आवश्यकता हो सकती है और पहले के वाद में पारित आदेश को या तो प्रारंभिक मुद्दे के रूप में या अंतिम सुनवाई पर लिया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रश्न का निर्धारण उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

24. यह कहना एक बात है कि उनके चेहरे पर वादपत्र में किए गए प्रकथन वाद हेतुक को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि हालांकि यह वाद हेतुक को प्रकट करता है, लेकिन यह एक कानून द्वारा वर्जित है।

२५- इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय इस संबंध में एक समान नहीं हैं। लेकिन फिर, व्यापक सिद्धान्त जो उससे निकाला जा सकता है, वह यह है कि न्यायालय उस स्तर पर किसी साक्ष्य पर विचार नहीं करेगा या तथ्य या विधि के विवादित प्रश्न में प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी कानून द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित पाया जाता है, जिसका अर्थ है, उसके विषय-वस्तु, वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय के निर्णयों की एक पंक्ति में उपरोक्त दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है। चर्च ऑफ क्राइस्ट न्यास एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट [चर्च ऑफ क्राइस्ट न्यास एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706 (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612], पी. सदाशिवम, जे. (उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 713-14, पैराग्राफ 10-11)

"१०. "उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जहां वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है, वहां दावा की गई राहत का मूल्यांकन कम किया जाता है और न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उसे ठीक नहीं किया जाता है, पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं किया जाता है और न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसे ठीक नहीं किया जाता है, जो किसी कानून द्वारा वर्जित है, अपेक्षित प्रतियां संलग्न करने में विफल रहता है और अभियोक्ता नियम 9 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। उपर्युक्त उपबंध के पठन से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति का विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, वादपत्र को रजिस्टर करने से पहले या प्रतिवादियों को सम्मन जारी करने के पश्चात या विचारण की समाप्ति से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

11- इस स्थिति को सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557] से इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिससे, संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते हुए, यह निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था (एससीसीपी पृष्ठ 560, पैरा 9)

9- "सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे वादपत्र में प्रकथन हैं। विचारण न्यायालय, मुकदमा को पंजीकृत करने से पहले या विचारण की समाप्ति से पहले किसी भी समय प्रतिवादी सम्मन देना जारी करने के पश्चात वाद के किसी भी चरण में सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के से शक्ति का प्रयोग कर सकती है। आदेश 7 सीपीसी के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के अन्तर्गत एक आवेदन पर फैसला करने के प्रयोजनों के लिए, वादपत्र में प्रकथन मुनासिब हैं- लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा उठाए गए अभिवचन उस चरण में पूरी तरह से असंगत होंगे, इसलिए, सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर फैसला किए बिना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश निचली न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के उपयोग से संबंधित प्रक्रियात्मक अनियमितता के अलावा कुछ नहीं हो सकता है।'

यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, विचारण न्यायालय को मुकदमे में प्रकथनों पर विचार करना होगा और इसका प्रयोग निचली अदालत द्वारा वाद के किसी भी चरण में किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में प्रकथन सारहीन हैं और वादपत्र में प्रकथनों/अभिवचनों की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय, वादपत्र में प्रकथन पर विचार करने की आवश्यकता है। उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा उठाए गए अभिवचन पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय मात्र वादपत्र प्रकथनों पर किया जाना है। इन सिद्धांतों को रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश सम्पति (रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लि. बनाम गणेश प्रॉपर्टी (1998) 7 एससीसी 184] और मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस (मायर (एच. के.) लि. बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100)।"

इसी प्रकार, सौमित्र कुमार सेन [सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644 (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329] में, सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के से एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा इस आधार पर खारिज करने का दावा किया गया था कि मुकदमा पूर्व न्यायिक व्यवस्था द्वारा वर्जित था। विचारण न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया: (सौमित्र कुमार सेन मामला (सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644 (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329), एससीसीपी 649, पैरा 9)

"9. प्रथम दृष्टया, यह देखा जा सकता है कि जहां तक स्थायी और आज्ञापक व्यादेश की राहत का संबंध है जो वाद हेतुक पर आधारित है। इसके साथ ही इस तरह की राहत पर विचारण न्यायालय द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब अभियोक्ता इस तरह का वाद लाने के लिए अपने अधिस्थिति को स्थापित करने में समर्थ हो। यदि अपीलकर्ता द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए प्रकथन सही हैं, तो ऐसा मुकदमा चलाए जाने योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार यह पहले ही पिछले दो मुकदमों में विनिश्चित किया जा चुका है कि प्रतिवादी-1 अभियोक्ता अपना हिस्सा लेने के पश्चात साझेदारी फर्म से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया है और यह

अपीलकर्ता (या अपीलकर्ता और प्रतिवादी 2) हैं जो एम/एस सेन इंडस्ट्रीज के मामलों का प्रबंधन करने के लिए हकदार हैं। यद्यपि इस स्तर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है, लिखित बयान में बचाव नहीं किया जा सकता है। आवेदन का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत निर्णय लेने के लिए वाद को देखना पड़ेगा। यह संभव है कि चतुराई से मसौदा तैयार किए गए मुकदमा से अभियोक्ता ने 2008 के वाद संख्या 268 के बारे में विवरण नहीं दिया, जो उसके विरुद्ध आदेश किया गया। उसने मुकदमा 103/1995 के बारे में, जिसमें निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है, उल्लेख करने का पूरी तरह से लोप कर दिया है। इस अर्थ में, वादी-प्रत्यर्थी 1 दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, यदि अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रकथन अंततः सही पाए जाते हैं, यद्यपि कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, लिखित बयान में प्रस्तावित इस तरह के बचाव पर सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 से आवेदन पर फैसला करते समय विचार नहीं किया जा सकता है।

कमला [कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा, (2008) 12 एस. सी. सी. 661] के प्रति निर्देश करते हुए, न्यायालय ने अग्रतर यह मत व्यक्त किया: (सौमित्र कुमार सेन मामला [सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644 (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329], एससीसीपी 650, पैरा 12)

"12. अपीलकर्ता ने पहले दो मामलों का उल्लेख किया है जो प्रतिवादी 1 द्वारा दायर किए गए थे और जिनमें वह विफल रहा था। ये न्यायिक रिकॉर्ड हैं। अपीलकर्ता पहले के दो वादों में अभिवचनों की प्रमाणित प्रतियां और साथ ही उन कार्यवाहियों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां दाखिल करके अपने प्रकथनों की शुद्धता को आसानी से प्रदर्शित कर सकता है। वास्तव में, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा दिनांक 31-3-1997 को पारित निर्णय और डिक्री, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) द्वारा दिनांक 31-3-1998 को पारित निर्णय की प्रति, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित डिक्री को बनाए रखने के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश, 2008 के वाद संख्या 268 में जूनियर डिवीजन द्वारा दिनांक 31-7-2014 को पारित निर्णय और डिक्री की प्रतियां अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर रखी हैं। पहले मुकदमा का निर्णय करते समय, विचारण न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रतिवादी 1 ने रु. 2, 00, 000 की राशि स्वीकार की थी और इसलिए, कथित मुकदमा विबंध, माफी और उपमति के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था। इस तरह के मामले में, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का सहारा लेना उपयुक्त नहीं था, लेकिन साथ ही, विचारण न्यायालय, मुद्दों को तैयार करने के पश्चात उन मुद्दों को उठा सकती है जो वाद की रखरखाव से संबंधित हैं और पहली बार में उनका फैसला कर सकती है। इस तरीके से अपीलकर्ता, या उस मामले में पक्षकार, लंबी कार्यवाही की अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, यदि अपीलकर्ता अंततः अपनी प्रस्तुतियों में सही पाया जाता है।

(जोर दिया गया)

यह कहते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 का सहारा लेना उचित नहीं था, इस विचारण न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय, मुद्दों को तैयार करने के पश्चात उन मुद्दों को उठा सकती है जो मुकदमों की

खरखाव से संबंधित हैं और पहली बार में उनका फैसला कर सकती है। अदालत ने कहा कि इस कार्यवाही से अपीलकर्ता को लंबी कार्यवाही से बचने में मदद मिलेगी।

१९- इस न्यायालय ने हाल ही में शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लि.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लि. बनाम केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया, (2020) 17 एससीसी 260], इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर द्वारा बोलते हुए, निचली अदालत द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत एक वादपत्र की अस्वीकृति के बारे में इस पीठ पर विचार कर रही थी कि यह परिसीमा द्वारा वर्जित था। न्यायालय ने सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557], चर्च ऑफ क्राइस्ट पूर्त न्यास [चर्च ऑफ क्राइस्ट न्यास एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 612] और यह मत व्यक्त किया कि: (चर्च ऑफ क्राइस्ट न्यास मामला [चर्च ऑफ क्राइस्ट न्यास एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706 (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612], एससीसी पी 714, पैरा 11)

"11. यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, विचारण न्यायालय को मुकदमापत्र में प्रकथनों पर विचार करना होगा और इसका प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण में विचारण अदालत द्वारा किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में प्रकथन सारहीन हैं और वादपत्र में प्रकथनों/अभिवचनों की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय, वादपत्र में प्रकथन पर विचार करने की आवश्यकता है। उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय मात्र वादपत्र प्रकथन पर किया जाना है। इन सिद्धांतों को रैंटाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश सम्पति (रैंटाकोस ब्रेट एंड कंपनी लि. बनाम गणेश प्रॉपर्टी (1998) 7 एससीसी 184] और मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस (मायर (एच. के.) लि. बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100)।

२०- उपर्युक्त प्राधिकारियों के अवलोकन पर, आदेश 7 के नियम 11 (घ) के से आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- (i) इस आधार पर मुकदमा को अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है, मुकदमा में मात्र प्रकथनों को ही वाद के लिए भेजा जाएगा;
- (ii) आवेदन के गुण-दोष का निर्णय करते समय मुकदमा में प्रतिमुकदमाती द्वारा की गई प्रतिरक्षा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए;
- (iii) पहला मुकदमा उन्हीं पक्षकारों या पक्षकारों के बीच था जिनके माध्यम द्वारा वे दावा करते हैं कि वे उसी शीर्षक से मुकदमा लड़ रहे थे और (i) यह कि इन मुद्दों का न्यायनिर्णयन किया गया था और (ii) बाद के मुकदमे में मुद्दा सीधे और काफी हद तक पहले के मुकदमे में था (iii) पूर्व का मुकदमा उन्हीं पार्टियों या पार्टियों के बीच था जिनके माध्यम से वे दावा करते हैं, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी कर रहे हैं और (iv) कि इन मुद्दों पर

न्यायनिर्णय किया गया और अंततः बाद के मुकदमा पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप द्वारा निर्णय लिया गया था, और

(iv) चूंकि पुनर्विलोकन के अभिवाक के न्यायनिर्णयन के लिए 'पिछले वाद' में अभिवचनों, मुद्दों और विनिश्चय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा अभिवाक आदेश 7 नियम 11 (घ) की परिधि के बाद होगा, जहां मात्र मुकदमा के कथनों का ही परिशीलन किया जाएगा।

21- वर्तमान मामले में, मुकदमा के अर्थपूर्ण पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पहले प्रत्यर्थी ने पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया था, तो उसे 13 मार्च, 2007 को संस्थित किए गए पहले वाद (ओएस संख्या 103/2007) के दूसरे प्रतिवादी के रूप में अभियोजित किया गया था। पहले प्रतिवादी ने पश्चातवर्ती वाद, ओएस १३८/२००८ किया, हालांकि उसे पहले वाद की जानकारी थी। बाद के वाद में वादपत्र, जो पहले प्रतिवादी द्वारा संस्थित किया गया था, इंगित करता है कि वह केएसएफसी के पक्ष में निष्पादित बंधक के बारे में अवगत था, कि केएसएफसी ने अपने देय राशियों की वसूली के लिए सम्पत्ति को बेचकर अपना प्रभार निष्पादित किया था और यह कि सम्पत्ति अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती के पक्ष में 8 अगस्त, 2006 को बेची गई थी। वास्तव में, वादपत्र में एक प्रकथन है कि इस बात की पूरी संभावना है कि पहले प्रतिवादी को ओएस १०३/२००७ में कब्जे के लिए एक डिक्री का सामना करना पड़ सकता है, जिसने पहले प्रतिवादी को बिक्री विलेख की वैधता को चुनौती देने के लिए वाद संस्थित करने के लिए मजबूर किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि नीलामी और उसके बाद के केएसएफसी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को कोई चुनौती नहीं दिए जाने के बारे में पिछले वाद में एक तर्क उठाया गया था, यह संभव है कि पहले प्रतिवादी ने तब अपने अधिकारों का प्रयोग करने का निर्णय लिया और बाद का मुकदमा किया। चाहे जो भी हो, मुकदमे को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पहले प्रतिवादी ने इस तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया है कि उस समय सम्पत्ति के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित था। यह भी ध्यान देने के लिए प्रासंगिक है कि पहले प्रतिवादी द्वारा वाद (ओएस नं. १३८/२००८) के संस्थित किए जाने के समय, ओएस नं. १०३/२००७ में सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की गई थी। इस प्रकार, उस समय ओएस नं. 103/2007 में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय नहीं किया गया था। इसलिए, वादपत्र, इसके सामने, किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं करता है जो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है कि इसे इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि यह पूर्व न्यायिक सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में अपने दृष्टिकोण में सही थे कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को वादपत्र में प्रकथनों के परे जाना होगा, और अभिवचनों, और ओएस नं. १०३/२००७ में निर्णय और डिक्री का अवलोकन करना होगा। आदेश 7 के नियम 11 के आवेदन का निर्णय वादपत्र के चार कोनों के भीतर किया जाना चाहिए। निचली विचारण और उच्च न्यायालय ने आदेश 7 के नियम 11 (डी) से आवेदन को खारिज करने में सही थे

२२- उपर्युक्त कारणों से, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि वादपत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) से अस्वीकार किए जाने के लिए दायी नहीं था और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करता है। यद्यपि हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया है कि क्या पश्चातवर्ती मुकदमा पुनः

न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। हम अपीलकर्ता को, जो केएसएफसी द्वारा आयोजित एक नीलामी में वाद सम्पत्ति के वास्तविक क्रेता के समनुदेशिती होने का दावा करता है, ओएस नं. १३८/२००८ में अपर सिविल न्यायाधीश, बेलगाम के समक्ष वाद की रखरखाव का मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। बेलगाम के अपर सिविल न्यायाधीश इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आदेश 14 के अन्तर्गत प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो प्रारंभिक मुद्दा उठाने के तीन महीने के भीतर इसका फैसला करेंगे। किसी भी स्थिति में, मुकदमा का अंतिम निर्णय 31 मार्च 2022 की बाहरी सीमा के भीतर किया जाएगा।“

१८- याचियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने राघवेन्द्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिंह (मृत) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट (2020) 16 एससीसी 601 में दी गई है। यद्यपि कथित निर्णय तथ्यों पर अलग है, क्योंकि उस मामले में अभियोक्ता ने स्वयं 06.03.1981 को एक पंजीकृत उपहार विलेख निष्पादित किया था और वर्ष 2002 में, लगभग 22 वर्षों के पश्चात उसके द्वारा घोषणा के लिए एक मुकदमा किया गया था कि 1981 में निष्पादित उपहार विलेख एक दिखावटी और फर्जी लेनदेन है और उपहार विलेख के बल पर प्रतिवादियों को कोई हक नहीं दिया गया था। इस प्रकार मुकदमे के प्रकथनों से यह स्पष्ट था कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।

1१९- वर्तमान मामले में, वादियों ने दलील दी मात्र कि याचियों के पक्ष में स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा बिक्री विलेख का मालिक होने का दावा करके धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया था और उन्हें धोखाधड़ी वाले बिक्री विलेख के बारे में फरवरी, 2008 में ही जानकारी प्राप्त हुई थी, जब वे बेचन सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गांव आए थे।

२०- इस प्रकार, क्या वादी ने फरवरी, २००८ में बिक्री विलेख के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जैसा की कथित है या नहीं, एक प्रश्न है, जिसे आदेश ७ नियम ११ के तहत आवेदन पर विचार करते समय तय नहीं किया जा सकता है सी पी सी। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, सीमा के संबंध में प्रश्न तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिसका निर्णय पार्टियों के साक्ष्य के बाद ही किया जा सकता है।

२१- इस प्रकार, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

२२- तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)